

जायसवाल समाज के होली मिलन समारोह में विराज सागर दास का किया गया सम्मान

वरिष्ठ संवाददाता (vol)

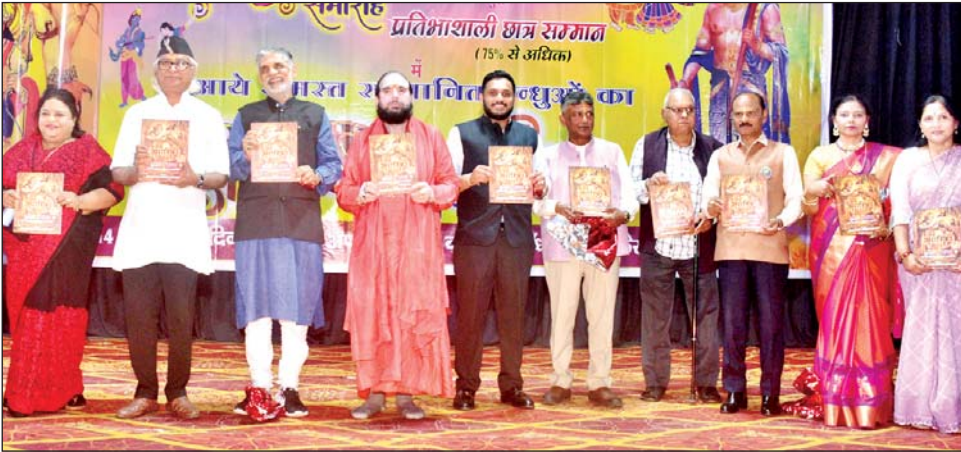
लखनऊ। जायसवाल समाज लखनऊ की ओर से शनिवार को कैसरबाग स्थित गांधी भवन में होली स्नेह मिलन, युवक-युवती वैवाहिक परिचय व प्रतिभाशाली छात्रों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्वामी संतोषानन्द महाराज, नीरजसिंह वरिष्ठ भाजपा नेता, विराज सागर दास, अध्यक्ष उग्र. ओलम्पिक संघ, अनुपमा जायसवाल, पूर्व मंत्री/विधायक, नीरज बोरा, विधायक, जायसवाल अटल गुप्ता, मेयर सुषमा खर्कवाल, नम्रता पाटक व पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया सहित व्यापार मण्डल अध्यक्ष संदीप बंसल, सुधीर



हलवासिया आदि कई विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी रही। इस मौके

पर समाज की ओर से प्रकाशित स्मारिका का विमोचन अतिथियों ने

किया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों की ओर से फैन्सी



इस व भारतीय शैली के परम्परागत नृत्य, देशभक्ति, मातृभक्ति, राधा-कृष्ण

रास व होली के अनूठे रंग को प्रस्तुत किया गया। सभी प्रतिभागियों को

सर्टिफिकेट व उपहार भी दिये गये। कार्यक्रम में लखनऊ के आस-पास

के जिलों से आये स्वजातीयजनों ने परस्पर होली मिलन व वैवाहिक परिचय में प्रतिभाग किया। मंच संचालन एडवोकेट अखिलेश जायसवाल, अध्यक्ष सेन्ट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ व रेखा जायसवाल महामंत्री की ओर से किया गया। ओम प्रकाश जायसवाल (संरक्षक), अध्यक्ष अजय जायसवाल, महामंत्री विनोद जायसवाल, कोषाध्यक्ष सर्वेश, राजेश (युवा अध्यक्ष), संगीता, अनीता, राखी, अनीता (नीतू), रश्मि, रेनु, रमा, सुमन, मोना, एडवोकेट संजय, वीरन्द, अमलेश, दुर्गाशंकर, समीर, एडवोकेट राजीव, सुनील, सी.ए. अरविन्द, विक्की, सचिन उपस्थित रहे।

90 हजार लाभार्थियों को मिलेगी पहली किस्त

20 लाभार्थियों को पीएम आवास स्वीकृति प्रमाणपत्र करेंगे वितरित, लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लगभग 90 हजार पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रथम किस्त जारी करेंगे।

वे इस धनराशि को डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के जरिए भेजेंगे। यह कार्यक्रम 16 मार्च को अपराह्न 04.30 बजे लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित किया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी 20 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाणपत्र भी वितरित करेंगे। इसके साथ ही वे फतेहपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, महाराजगंज तथा देवरिया के एकझएक लाभार्थी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल संवाद भी करेंगे और उनसे योजना के लाभ एवं अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 एक मांग आधारित योजना है। इसके अंतर्गत सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को



चरणबद्ध तरीके से आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सुरक्षित एवं पक्का आवास उपलब्ध कराना है, जिससे सबके लिए आवासह की परिकल्पना को साकार किया जा सके। यह कार्यक्रम केवल धनराशि हस्तांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश सरकार की सबके लिए आवास की संकल्पना को धरातल पर उतारने की दिशा में उत्तर प्रदेश की स्पष्ट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।

राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से बड़ी संख्या में शहरी गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

सिंचाई एवं जल संसाधन प्रबंधन में एआई के उपयोग से आयेगी पारदर्शिता

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग विषय पर कार्यशाला का आयोजन

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सिंचाई एवं जल संसाधन प्रबंधन को अधिक आधुनिक, वैज्ञानिक तथा तकनीक आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (अक) के उपयोग विषय पर आज यहाँ वाली भवन, लखनऊ में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए जलशक्ति मंत्री श्रीरवतर्न देव सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (अक) जैसी उन्नत तकनीक शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा परिणामोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं जलसंसाधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में एआई आधारित प्राणियों के उपयोग से



नहरों के संचालन, जल वितरण की रीयल-टाइम निगरानी, बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली, जल संसाधनों के वैज्ञानिक आकलन तथा अवसरचना के प्रभावी प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभागीय कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीकों को अपनाने तथा तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक्स तथा डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी उन्नत तकनीकों के समुचित उपयोग से जल संसाधनों के संरक्षण, सिंचाई क्षमता में वृद्धि तथा

विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सुधार संभव हुआ है।

प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने कहा कि एआई के उपयोग से विभागीय कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया एआई के उपयोग करने में मैनुअल चेकिंग अनिवार्य रूप से करें जिससे सम्भावित त्रुटियों से बचा जा सकेगा। कार्यशाला के दौरान विषय विशेषज्ञों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न आयामों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। विशेषज्ञों ने एआई आधारित डेटा

विक्षेपण, बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली जल संसाधन प्रबंधन के लिए स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, नहर नेटवर्क के संचालन में डिजिटल तकनीकों के उपयोग तथा भविष्य में उभरने वाली तकनीकी संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी साझा की। कार्यक्रम के अंत में यह विश्वास व्यक्त किया गया कि इस प्रकार की पहलें विभाग में तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देंगी तथा आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग से प्रदेश में सिंचाई एवं जल संसाधन प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी, दक्ष एवं भविष्य उन्मुख बनाया जा सकेगा।

इस अवसर पर प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग सहित विभाग के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित विभिन्न विषय विशेषज्ञ एवं वक्ता उपस्थित रहे।

आरटीई के तहत लाखों बच्चों के लिए खुले निजी स्कूलों के दरवाजे

प्रथम और द्वितीय चरणों में 1.56 लाख से अधिक बच्चों को मिला प्रवेश

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा दिलाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आवेदन, सत्यापन और लॉटरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है।

प्रदेश में आरटीई के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय चरण में मिलाकर 1.56 लाख से अधिक छात्रों को निजी स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित किया गया है। प्रथम चरण में लगभग 1.09 लाख सीटों का आवंटन किया जा चुका है जबकि द्वितीय लॉटरी में



- लखनऊ, कानपुर नगर और आगरा में सर्वाधिक छात्रों को मिला प्रवेश का अवसर**

47 हजार से अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिला है। इस प्रकार बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर सुनिश्चित किए गए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में

आवेदन सत्यापित किए गए। आरटीई के तहत सर्वाधिक प्रवेश

लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मुरादाबाद और बुंदेलशहर जैसे जनपदों में हुए हैं, जहां हजारों बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिला है। इसी प्रकार अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फरीदाबाद और बरेली जैसे जिलों में भी हजारों बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश का अवसर मिला है। आरटीई अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों

में निर्धारित सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। योगी सरकार ने इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया है ताकि चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना ​​है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज के हर वर्ग के बच्चों तक पहुंचनी चाहिए।

इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी निजी विद्यालयों में पढ़कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया के आगामी चरण भी जल्द पूरे किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके।

प्रदेश में तीन माह में बने करीब 18 लाख नये आयुष्मान कार्ड

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत छूटे पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ देने के लिए योगी सरकार प्रदेश भर में विशेष अभियान चला जा रही है। अभियान की शुरूआत बीते साल 25 नवंबर को हुई। यह 25 दिसंबर, 2025 तक चला। इस दौरान 5 लाख 52 हजार से अधिक कार्ड बनाए गए। अभियान की सफलता को देखते हुए इस साल 15 जनवरी से दोबारा विशेष अभियान शुरू किया गया, जो वर्तमान में चल रहा है। विशेष अभियान की अवधि में अब तक 17 लाख 94 हजार से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। अभियान के दौरान विशेष रूप से आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के साथ उनके परिवार के कार्ड बनाए जा रहे हैं। अभियान के दौरान सबसे अधिक बरेली में कार्ड

- बरेली, जौनपुर और आगरा में विशेष अभियान के दौरान सबसे अधिक बनाये गये कार्ड**



बनाए गए। इससे बरेली कार्ड बनाने में पूरे प्रदेश में पहले, जौनपुर दूसरे और आगरा तीसरे स्थान पर हैं।

साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य बन चुका है। योजना के तहत प्रदेश में अब तक लगभग 5.64 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे करोड़ों परिवारों को सलाह

- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं और उनके परिवार के कार्ड बनाए गए**

पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के करीब 25 लाख 70 हजार बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि योगी सरकार वंचित पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान

चला जा रही है। यह अभियान पहले 25 नवंबर से 25 दिसंबर, 2025 तक संचालित किया गया। अभियान की सफलता को देखते हुए इसे इस साल 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक विस्तारित किया गया है। अभियान के तहत 12 मार्च तक 17 लाख 94 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

अभियान को स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से संचालित किया जा रहा है। ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से पात्र परिवारों तक पहुंच बनाकर उनका सत्यापन किया गया और मौके पर ही आयुष्मान कार्ड बनाए गए। अभियान के दौरान सबसे अधिक बरेली ने 1,12,855 कार्ड बनाकर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह जौनपुर 83,042 कार्ड बनाकर दूसरे, आगरा 76,702 कार्ड बनाकर तीसरे स्थान पर है जबकि प्रयागराज

74,252 कार्ड बनाकर चौथे और आजमगढ़ 70,266 कार्ड बनाकर पांचवे स्थान पर है। साचीज की एसीईओ डॉ. पूजा यादव ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं तथा उनके परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 4.28 लाख आशा कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्य योजना के दायरे में आते हैं। इनमें से 12 मार्च तक करीब 3.24 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अभी लगभग 1.03 लाख लोगों के कार्ड बनना शेष है। इस दौरान सबसे अधिक कुशीनगर में 6,620 कार्ड बनाए गए। इसी प्रकार लगभग 2.17 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और उनके परिवारों में से 1.53 लाख के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि लगभग 64 हजार लाभार्थियों के कार्ड बनने बाकी हैं।

आजमगढ़ 70,266 कार्ड बनाकर पांचवे स्थान पर है। साचीज की एसीईओ डॉ. पूजा यादव ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं तथा उनके परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में लगभग

4.28 लाख आशा कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्य योजना के दायरे में आते हैं। इनमें से 12 मार्च तक करीब 3.24 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अभी लगभग 1.03 लाख लोगों के कार्ड बनना शेष है। इस दौरान सबसे अधिक कुशीनगर में 6,620 कार्ड बनाए गए। इसी प्रकार लगभग 2.17 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और उनके परिवारों में से 1.53 लाख के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि लगभग 64 हजार लाभार्थियों के कार्ड बनने बाकी हैं।



कुमार तिवारी ने कहा कि बजट सत्र के भीतर यह विधेयक नहीं लाया गया तो संसद का घेराव भी वकीलों के द्वारा तय है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार अधिवक्ताओं को वोट बैंक से इतर मानने की भूल कर रही है। सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश मिश्र व संयोजन लखनऊ मण्डल अध्यक्ष आनन्द त्रिपाठी तथा संचालन अधिवक्ता शैलेन्द्र तिवारी ने किया। आमसभा को वरिष्ठ अधिवक्ता बृजेश श्रीवास्तव, विजय पाल, विपिन शुक्ल, अबरार अहमद, हरिश्चंद्र पाण्डेय ने भी

संबोधित करते हुए मांग के समर्थन में आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया। एसोसिएसन के जिला इकाई अध्यक्ष जितेन्द्र तिवारी ने सुरक्षा अधिनियम के मसौदे से साथियों को अवगत कराया।

इस मौके पर कौशलेंद्र वर्मा, आयुष त्रिपाठी, सत्यम त्रिपाठी, हरकृष्ण तिवारी, टीपी त्रिपाठी, डीपी सिंह, अशोक दीक्षित, टीके बोस, शैलेन्द्र शुक्ला, दिलीप दुबे आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। यह जानकारी एसोसिएसन के जिला इकाई अध्यक्ष दीपेन्द्र तिवारी द्वारा जारी विज्ञप्ति में दी गयी है।

